अध्यक्ष महोदय : आप ने इस प्रश्न को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है। जब हिन्दी का मामला आवे, तब इस बारे में पूछिएगा।

श्री झारखण्डे राय : क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि अपनी भाषा नीति को स्पष्ट करते हुए जब भारत सरकार ने प्रदेशों को निर्देश दिये हैं, जिन में तामिलनाड़ भी शामिल है, क्या इस तरह का कोई निर्देश दिया गया है कि कोई भी सूबा तामिलनाडु वगैरह भी यदि चाहें तो केन्द्रीय सरकार को अपनी मातृभाषा में अपनी बातें लिख सकते हैं? क्या ऐसा कोई आदेश दिया गया है या नहीं?

श्री राम निवास मिर्धा : केन्द्र सरकार ने भाषा सम्बन्धी मामलों पर राज्य सरकारों को कोई आदेश नहीं दिये हैं। जो भाषा नीति है, वह केन्द्रीय सरकार के स्वयं के कार्य के सम्बन्ध में है। राज्य सरकारों की क्या भाषा नीति हो, यह उन पर छोड़ दिया गया है, जैसा वे चाहें कर सकते हैं।

श्री झारखण्डे राय : मैंने पूछा था केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के आपस के पत्राचार में क्या सूबाई सरकार अपनी मातृभाषा में लिख सकती है, ऐसा कोई आदेश है?

श्री राम निवास मिर्धा : केन्द्रीय सरकार अंग्रेजी और हिन्दी में अपना कार्य करती है और जिन भाषाओं में केन्द्रीय सरकार के पास पत्र आते हैं—यदि हिन्दी में मिलते हैं तो कोशिश की जाती है कि हिन्दी में उत्तर दिया जाए। लेकिन सरकारी भाषायें दो हैं—हिन्दी और अंग्रेजी, इसलिये किसी अन्य भाषा में पत्र भेजने और उसी भाषा में उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि केन्द्रीय सरकार का काम हिन्दी और अंग्रेजी में ही चलता है।

SHRI JYOTIRMOY BOSU : It is agreed irrevocably that the use of English language for communications between the Central Government and State Governments and non-Hindi speaking States until the latter choose to correspond in Hindi remains. In view of the fact that complaints are coming from the highest quarters, will the hon. Minister consider and agree to institute an inquiry into the matter so that the whole thing could be thoroughly enquired into and a decision taken ?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : It is perfectly clear that no enquiry is necessary. We are not contravening any provisions of the Resolution passed by this House or the assurances given here. (*Interruption*) The Chief Minister of Tamil Nadu is reported to have said that the Central Government has told the State Governments that all letters addressed to the Union Ministers should be in Hindi. It is not correct. We have not issued any instructions of this nature.

Industrial Survey of Madhya Pradesh

O

*324. SHRI G. C. DIXIT† :
SHRI ARVIND NETAM :

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state :

(a) whether any industrial survey of Madhya Pradesh has been conducted; and

(b) if so, the salient features thereof and the action proposed to be taken by Government on the Survey Report ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD) : (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) Yes, Sir. Recently the Joint Institutional Study Team set up by IDBI, IFCI, ICICI and the Reserve Bank of India surveyed the State and prepared a report on its industrial potential.

(b) The report brings out that a central geographical position conferring benefits of

market in the neighbouring areas and safety from strategic point of view, very large deposits of mineral resources, particularly iron ore, vast forest resources in a widespread area, a fairly comfortable food position coupled with the immense scope for furthering agricultural production, a lower density of population, surplus power and above all, the climate for industrialisation generated by large investments inducted in public sector projects like Bhilai Steel and Heavy Electricals (India) Limited (Bhopal) are major favourable factors conducive to industrialisation that the State enjoys. On the other hand, a relatively backward economy marked by a low *per capita* income and income generation, an excessive dependence on agriculture, lack of industrial tradition, inadequate transport system accentuated by the wastness of the area rendering exploitation of natural resources and marketing of produce difficult, relatively costly power structure, the dearth of legal entrepreneurship and inadequacy of trained and skilled labour have been the main barriers affecting rapid industrial growth in the State. The pace of industrialisation in the years to come, for which the State has undoubtedly unlimited potential, greatly depends on the speed with which these handicaps are removed and the favourable factors are taken advantage of.

The survey has also identified the industrial projects which hold promise of coming up in the foreseeable future.

The report is now upder examination of the State Government and will soon be discussed by the Committee of Direction to finalise the strategy of follow up.

श्री गंगा चरण दीक्षित : जैसा कि स्टेटमेन्ट में बताया गया है कि मध्य प्रदेश में, भारत के मध्य में स्थित होने के कारण, भौगोलिक परिस्थिति के कारण तथा साथ ही साथ औद्योगिक दृष्टि से भी बहुत कुछ औद्योगिक विकास होने की गुंजाइश है तो क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी कदम कब तक उठायें जायेंगे और यदि नहीं उठाये जायेंगे तो क्यों नहीं?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : जो विवरण सभा पटल पर रखा गया है उसमें अन्य बातों के अलावा इस बात को पूरे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देने की जरूरत है जिनमें से एक है यातायात, अर्थात वहां पर यातायात की सुविधा को बढ़ाना, दूसरे वहां उद्योगों की संख्या बढ़ाने के लिये बिजली की दर को कम करना। इनके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार को इस प्रकार का वहां वातावरण बनाना है जिससे उद्योगों का विकास हो सके। एक एक कर इन बातों पर कदम उठाने की पहल की जा रही है और उसके बाद तेजी से विकास होगा।

SHRI R. S. PANDEY: Madhya Pradesh is considered to be a backward State so far as industrial development is concerned, so far as the other economic aspects are concerned. There are certain districts like Bastar where raw materials like bamboo are available. In the first week of June, the hon. Prime Minister visited that area and she has seen the condition of the poor Adviasis there. May I know whether any letter of intent has been issued to any firm to find out the potentiality and put up a factory—a paper factory? If it has been issued to a private concern, what objection Government has got to put up an industry in the public sector?

SHRI SIDDHESHWAR PRASAD: As far as Bastar district is concerned, it is a backward district and raw material available there is suitable for paper industry. The Bangur Group of industries has been given a letter of intent in the Joint Sector. We hope that this industry will come up in that backward district of Bastar.

SHRI R. S. PANDEY: The paper will will have sophisticated machinery and there will hardly be any scope for employment of people in this automation. May I know whether, before they issued the letter of intent, they examined the potential of employment? This is also very important so far as Madhya Pradesh is concerned.

SHRI SIDDHESHWAR PRASAD: It is completely a different question about employment potential, etc. If the hon. Member wants to have any specific information on this point, he may ask a separate question.

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के उस वक्तव्य की ओर गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम हर जिले में दो नये उद्योग देंगे। क्या उस सम्बन्ध में भारत सरकार को मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से कोई पत्र मिला है? मध्य प्रदेश में पानी है, वहां काफी अच्छी सहूलियतें मौजूद हैं इसको ध्यान में रखते हुए, जो आपने बताया है कि यातायात की काफी कमी है और उसको बढ़ाने का विचार रखते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि चौथी पंचवर्षीय योजना में यातायात के लिए कितनी सड़कों का निर्माण करना चाहते हैं—क्या ऐसा कोई लक्ष्य आपने अपने सामने रखा है? इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है और केन्द्र के सहयोग से मध्य प्रदेश में कितने उद्योग खोलने वाले हैं?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री का बयान मैंने नहीं देखा है। जो विवरण सभा पटल पर रखा गया है वह उस रिपोर्ट पर आधारित है जोकि आई० डी० बी० आई०, आई० एफ० सी० आई०, आई० सी० आई० सी० आई० तथा रिजर्व बैंक टीम की ज्वाइन्ट सर्वे द्वारा प्रस्तुत की गई है। उसमें इन बातों का उल्लेख किया गया था जिनसे मध्य प्रदेश में तेजी से उद्योगों का विकास नहीं हो रहा है। अतः उस रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार के सामने इन बातों को रखकर उनसे चर्चा करने के लिए उक्त टीम द्वारा समय निश्चित किया जा रहा है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मंत्री जी ने उत्तर में स्वीकार किया है कि वहां यातायात की कमी है, उसका विकास करना है तो मैं जानना चाहता हूं चौथी योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में आप कितनी सड़कों का विकास करना चाहते हैं, इसके सम्बन्ध में आपने क्या लक्ष्य बनाया है?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : जहां तक यातायात का प्रश्न है, निश्चित रूप से तो यातायात मंत्रालय ही बता सकता है कि मध्य प्रदेश में यातायात की सुविधा का विकास करने के लिए क्या योजना है।

SHRI D. BASUMATARI: Wherever any industry is established in the tribal area because raw materials are found in those areas, the tribal people are ousted from their homes and hearths. This being the case, may I know from the hon. Minister whether he has approached the planning Commission to see that, wherever such a project is taken up, the ousted people are rehabilitated with land for land?

SHRI SIDDHESHWAR PRASAD: There is a programme for rehabilitation wherever industries are set up in such districts. If there is any specific project in the mind of the hon. Member and if he has certain specific issues related to that, he may certainly ask a separate question.

SHRI D. BASUMATARI: What about Baladilla? A number of people have been ousted from that place.

MR. SPEAKER: This is a question regarding Madhya Pradesh. Please do not think that the Minister is in the dock and has to give all the information; that should not be the spirit while asking the question.

श्रीमती सहोदरा बाई राय : मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से पूछना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश में सागर इलाके में कोई सीमेन्ट का कारखाना खोलने वाले हैं क्या? यदि हां, तो कब तक खोलेंगे?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई सूचना